THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): All these things, you can speak when we have the discussion. Kindly conclude now.

श्री मूलचन्द मीणा: सर, मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार, राजस्थान के बाढ़ से पीड़ित लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए , उन की क्षति-पूर्ति के लिए राजस्थान सरकार ने जो पैसा मांगा है, वह उतना पैसा दे जिससे कि वहां पीड़ित लोगों को राहत मिल सके। महोदय, वहां बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के अंदर कई प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। उन से प्रभावित लोगों के लिए दवाइयों की व्यवस्था की जाए। साथ ही यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार को बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए, प्यासों को पानी पहुंचाने के लिए जो पैसा दिया जाता है उस का सदुपयोग नहीं किया जाता। मैं चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार उस पर निगरानी रखे। बाढ़-पीड़ितों के लिए जो पैसा दिया जाता है, वह बाढ़-पीड़ितों को ही मिले।

श्री शिव चरण सिंह: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मीणा जी ने जो कुछ कहा है, उस में सारे फैक्ट्स उन को पता नहीं है। वहां जितना नुकसान हुआ है, वह उन्हें मालूम नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बात सत्य कही कि भारत सरकार से नेशनल कैलेमिटी और रिलीफ के नाम पर जो वहां की सरकार ने मांगे हैं, वह 300 करोड़ रुपये कम हैं। वहां 500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

उपसभाध्यक्ष जी, राजस्थान में 25 जून को बारिस आती है और 25 जून के पश्चात् 552 एम.एम. का हमारे यहां एवरेज है। इस में जून के महीने में 29 एम.एम. बारिस एवरेज आती है लेकिन इस बार 76 एम.एम. बारिस हुई है। महोदय, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जौधपुर, अलवर और भरतपुर में सारी बारिस हुई। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): All the details can be given in the discussion. Now kindly just say that you are associating.

श्री शिवचरण सिंह: महोदय, यहां पूरे डिटेल्स नहीं दिए गए हैं। मैं वहीं का रहनेवाला हूं और मुझे मालूम है कि वहां लोगों की क्या दुर्दशा हुई है। वहां 900 पशु मर गए हैं, हजारों एकड़ जमीन कट गयी है या लैंड इरोजन हुआ है। वहां 500 करोड़ रुपये की सहायता तुरंत चाहिए। ...(व्यवधान)... यह सहायता अगर नहीं दी गयी तो यह भारत सरकार की जिम्मेदारी होगी और भारत सरकार पर यह दोषारोपण होगा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के नाते वह नेशनल कैलेमिटी फंड से और रिलीफ फंड से वहां के लोगों की मदद नहीं करना चाहती है। ...(व्यवधान)...

श्री सतीश अग्रवाल: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, कल 11 जुलाई को तारांकित प्रश्न संख्या-25 का श्री चतुसनन मिश्र जी ने जो उत्तर दिया है, उस में 13 राज्यों में बाढ़ से हुए नुकसान का पूरा ब्यौरा दिया गया है। उस में आसाम के बारे में एलीमल्स लॉस्ट, हाउसेस गटेड/डैमेज्ड "जीरो-जीरो" है। इस का मतलब यह हुआ कि आसाम गवर्नमेंट ने आप को कोई सूचना नहीं दी है। तो यह आसाम सरकार की हालत है जिसकी आप पैरवी कर रहे हैं। इस सारी सूची में 13 राज्यों - एनीमल लॉस्ट की जो संख्या है, उस में राजस्थान की संख्या सर्वाधिक 4723 है जोकि किसी राज्य में नहीं है। मैं राजस्थान के बारे में ज्यादा विचार उस समय जब कि बहस होगी रखूंगा। मेरे पास पूरा मेमोरेंडम है। उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान में इस बार की बाढ़ से जोधपुर, बाड़मेर, वेस्टर्न राजस्थान का डेजर्ट इलाका, वहां इस बार 600 एम॰ एम॰ की बारिस हुई है जोकि आज तक कभी हुई नहीं। राजस्थान में इस बार जितनी बरसात जयपुर, जेसलमेर, जोधपुर, बाडमेर में हुई, यही अच्छी बात है, लेकिन इतनी अप्रत्याशित रूप से कि सारे क्षेत्र में छह-छह दिन पानी भरा रहा और जिससे नुकसान हुआ इसलिए मेरा निवेदन है कि 500 करोड़ रुपया राजस्थान को राहत के रूप में देने की व्यवस्था कराएं तो इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा।

RE. DEVASTATION CAUSED BY FLOODS IN VARIOUS PARTS OF THE COUNTRY, PARTICULARLY IN ASSAM AND NORTH-EAST.

श्री मतंग सिंह (असम)- उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान असम में आई भयंकर बाढ़ की ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा। असम के धमाजी जिले में, लखीमपुर जिले में, धुबरी जिले में और मेरे गृह जिला डिब्रुगढ़ में बाढ़ का भयंकर प्रकोप हुआ है और केन्द्र सरकार यहां हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। केन्द्र सरकार ने न तो अभी तक बाढ़ का जायजा लेने के लिए कोई उपयुक्त टीम ही वहां भेजी और न ही केन्द्र सरकार की तरफ से उसके किसी मंत्री ने वहां मुआयना किया।

उपसभाध्यक्ष महोदय, देश के अन्य राज्यों में बाढ़ से क्षतिग्रस्त इलाकों का दौरा करने के लिए केन्द्र सरकार से प्रधानमंत्री स्वयं और इनके कई कैबिनेट मंत्रियों ने दौरा किया। प्रधानमंत्री ने तो अपने कोष से उन राज्यों में राहत के लिए राशि का अनुमोदन भी किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम असमवासियों के लिए न तो केन्द्र सरकार के किसी मंत्री का दौरा हुआ और न प्रधानमंत्री के कोष से किसी राशि की व्यवस्था की गई है। इस तरह का केन्द्र सरकार के सौतेलेपन का व्यवहार हमारे साथ होता रहा है। यही कारण है कि हम लोग अपने आपको उपेक्षित महसूस करते हैं। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष महोदय, पिछले पांच सालों में नरसिंह राव की सरकार ने उत्तर-पूर्वी राज्यों और असम में कुछ विकास के कार्यक्रमों को आरंभ करवाया और करने की कोशिश की थी। आशा थी कि युनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट उन कार्यक्रमों को पूरा करेगी। हमने युनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के मिनिमम प्रोग्राम में देखा कि गरीबों को ऊपर उठाने की बातें कही गई है, कमजोर तबके के लोगों को ऊंचा उठाने की बात कही गई है, इकोनोमिकली बैकवर्ड इलाके के लोगों को ऊंचा उठाने की बात कही गई है। मान्यवर, असम से बड़ा इकोनोमिकली बैकवर्ड एरिया और कौन हो सकता है? हम देश के एक रिमोट कार्नर प्लेस में बसे हुए हैं। जब आप इकोनोमिकली बैकवर्ड की बात करते हैं, तो आप उधर भी देखिए। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि बाढ़ से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कितने लोगों की जाने गई हैं? इस सदन में कृषि मंत्री बैठे हुए हैं, मैं इनसे यह जानकारी चाहूंगा कि बाढ़ से कितने एकड़, कितने हैक्टेयर जमीन में खड़ी हमारी फसल बरबाद हुई है? हमारे असम में मुख्य खेती है धान की। हमारे यहां डिब्रूगढ़, धमाजी, लखीमपुर, धुबरी, ब्रह्मपुत्र वैली में हमारी खेती की फसल सब नष्ट हो गई। केन्द्र सरकार ने अभी तक न कोई अधिकारियों की टीम मुआयना करने के लिए असम में भेजी, न कोई जांच हुई। मैं जानना चाहूंगा कि जो लोग बाढ़ से मौत के आगोश मे चले गए, उनके परिवारों के राहत के लिए केन्द्र सरकार ने क्या उपाय किए? ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी अभी हमारे मित्र रामदास अग्रवाल जी ने राजस्थान के लिए कहा कि 46 करोड़ रुपया दिया गया बाढ़ से पीड़ित लोगों के रिहेबलिटेशन के लिए, लेकिन असम के लिए केन्द्र सरकार ने एक पैसा भी नहीं दिया । ...(व्यवधान)...

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: सर, मंत्री महोदय कहें, उससे पहले एक मिनट। ...(व्यवधान)

VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): The Minister wants to reply. (*Interruptions*) We are going to discuss the flood situation separately.

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस प्रश्न पर जब माननीय सदस्य विचार करेंगे तो उस दिन कहूंगा, लेकिन यह तय किया है, कल हमने साइन कर दिया है, हरेक राज्य का, 13 राज्यों की चर्चा की गई है कि कितना-कितना डेमेज हुआ है, क्या रिपोर्ट है, कितना आपको पैसा दिया गया है, सब जानकारी हम आपको पहले ही दे देंगे ताकि आप और अच्छी तरह से बहस कर सकें। हमारी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। ...(व्यवधान)...

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश): मध्यप्रदेश भी शामिल है?

श्री चतुरानन मिश्र: मध्यप्रदेश की सरकार ने कोई रिपोर्ट नही दी। ...(व्यवधान)... आप सुन तो लिजिए। ...(व्यवधान)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया (बिहार): सुपर कम्प्युटर आप लगाए हुए हैं और आप राज्य से रिपोर्ट मंगाइएगा?

...(व्यवधान)... मेट्रोलोजिकल डिपार्टमेंट आपको रिपोर्ट दे देगा। ...(व्यवधान)...

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे (गुजरात): कोई टीम भेजी गई स्टेट में ? ...(व्यवधान)...

श्री चतुरानन मिश्र: आप सुन तो लिजिएगा तब कहिएगा। हम आपकी सहायता के लिए चाहेंगे, इन्होंने इंफोरमेशन जो जो चाही हैं असम की, वह कल सवेरे आपको पहुंचे ..... ताकि आपको बहस करने में सुविधा हो, आपके ही लिए हम आपको दे रहे हैं। क्योंकि उन्होंने पूछ लिया मध्य प्रदेश का तो हम ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): It is his maiden answer during Zero Hour.

श्री चतुरानन मिश्र: मेडन तो सवेरे ही हो गया। अब हम एक-दो बात आपसे कह देना चाहते हैं, इसके बाद जैसा आप निर्णय करेंगे वैसा होगा। पहली बात यह है, यह तो ठीक है कि राजस्थान में बहुत ज्यादा क्षति हुई है, प्रधान मंत्री गए भी थे, देखा भी था और उन्होंने कुछ अपने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से दिया। वह हमारे नियंत्रण में नहीं है। जो तरीका है वह हम आपको समझा देते हैं। एक भी राज्य ने यह नहीं कहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए मदद कीजिए। एक भी राज्य ने नही कहा है।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया। बिहार ने भी?

श्री चतुरानन मिश्र: किसी ने भी नहीं लिखा है। ...(व्यवधान)...

श्री मतंग सिंह: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा ... (व्यवधान)...

श्री रामदास अग्रवाल: एक मेमोरेंडम सरकार ने दिया है जिसमें 300 करोड़ रुपए की मांग की है। ...(व्यवधान)...

श्री मतंग सिंह: क्या इन्होंने असम सरकार से एसा पूछा है कि राहत कोष के लिए उनको पैसे की आवश्यकता है या नहीं?

श्री चतुरानन मिश्र: आज ही सवेरे असम के खाद्य एवं राजस्व मंत्री ...(व्यवधान)... राजस्व मंत्री श्री प्रमोद गगोइ जी आज ही सवेरे मुझसे मिले और हमने उनको बताया है। उन्होंने भी पूरा रूपया खर्च करके हमारे पास अभी रिपोर्ट नहीं भेजी है कि पूरा रूपया खर्च हुआ है।

राजस्थान के हमारे माननीय सदस्य ने जो कहा, तो वह 300 करोड़ रुपया नहीं मांगा था, प्राइम मिनिस्टर को जो दिया था एक लैटर के तौर पर, उसमें है 100 करोड़ रूपए की मदद और 300 करोड़ रूपए की क्षति। माननीय सदस्य क्षति को मदद में बदल रहे हैं।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी (उत्तर प्रदेश): आपकी सदृश्यता पर निर्भर है। ..(व्यवधान)..

श्री चतुरानन मिश्र। अब सुनिए न, सूचना क्यों नहीं देने देते। दूसरे हम आपसे कहना चाहेंगे कि अभी 10वें फाइनेंस कमीशन ने इन-बिल्ट सिस्टम बना दिया है बाढ़ सहायता के लिए। 7000 करोड़ रुपए का पांच वर्ष के अंदर खर्च करने का एक कोरपस फंड बना दिया है जिसमें राज्य सरकार के पास 6,300 और कुछ करोड़ रुपया उनके पास है, हमारे पास सिर्फ 700 करोड़ रुपया है, इसी में से हमको देना है। अब उस क्राप्सकोष में से जब जरूरत हो, आलमोस्ट ऑटोमेटिक आप रुपया ले लेते हैं। सिस्टम बना हुआ है, फाइनेंस कमीशन ने बना दिया है। आपको लेना है, ले लीजिए उसमें से, आपको चाहिए तो हम आपको एडवांस भी दे सकते हैं उसमें से।

श्री एस॰एस॰ सुरजेवाला: बहस के जवाब में ये सारी बातें आ जाएंगी तफ्सील से, ज़ीरो ऑवर का समय बहुत कम है।

श्री चतुरानन मिश्र: आप ही लोग पूछ रहे हैं तो हम जवांब दे रहे हैं और सभापति महोदय पैसे के अभाव में किसी को नहीं मरने दिया जाएगा, कोई तकलीफ में नहीं रहेगा। आप हमको बतला दीजिए कि जो रुपया दिया गया है, वह खर्च हो गया है, इसके बाद आप हमसे पता कीजिए।

सभापति महोदय, सेंट्रल टीम तब जाती है जब राज्य से एक मेमोरेंडम आता है। ...(व्यवधान)...

श्री मतंग सिंह: कहां से?

श्री चतुरानन मिश्र: स्टेट गवर्नमेंट से और कहां से? माननीय सदस्य मेमोरेंडम भिजवाएं। किसी भी स्टेट ने अभी तक मेमोरेंडम नहीं भेजा है क्योंकि सबके पास रुपया है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि रुपए का दुरूपयोग राज्य सरकार न करे, यह अधिकार तो हमको नहीं है - यूं तो आप जानते हैं कि संविधान के मार्फत् आपको अधिकार है - लेकिन 10वें फाइनेंस कमीशन के डायरेक्टिव्स हैं कि ऑडिटर जनरल जो होंगे वहां के, उनको यह अधिकार दिया गया है कि अगर दुरूपयोग होता है तो वे तुरंत ब्रेक लगाएं, रोक लगाएं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Minister, you can reply elaborately when we will have a discussion on the subject. The remaining part of the reply you can give later ...*(Interruptions)*...

SHRI PARAG CHALIHA (Assam): Sir, we are all speaking of temporary measures. *(Interruptions)*....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): He has answered all your points. *(Interruptions)*....

श्री पराग चालिहा: मतंग सिंह जी, मैं आपकी तरफ से कहता हूं . . .(व्यवधान) Sir, there were some recommendations by the Planning Commission and a full-fledged committee was constituted under the Chairmanship of Shri L.C. Jain some eleven years back. A Brahmaputra Board was constituted and in the report made by the L.C. Jain Committee, which consisted of members of Parliament from both the Houses, there was a recommendation that we should activate the Brahmaputra Board. I want to know whether any importance has been given to that report. *(Interruptions)*....

SHRI S.S. SURJEWALA: Sir, I am on a point of order. *(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): I am going to adjourn the House. *(Interruptions)*...

SHRI S.S. SURJEWALA: Sir, there should be some debate on floods. *(Interruptions)*... There should be a regular debate on floods. *(Interruptions)*.....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI NARAYANASAMY) : Now the remaining Zero Hour buisness and the Special Mentions will be taken up after lunch till 2.30 P.M. The House is adjourned till 2.05 P.M.

The House then adjourned for lunch at six minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at eight minutes past two of the clock, **The Vice-Chairman (Shri Triloki Nath Chaturvedi)** ***in the Chair.***

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: सभापति महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज स्पेशल मेंशन लिया जाएगा?

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): जी हां, आपके सहयोग पर यह निर्भर करेगा, क्योंकि अभी जीरो ऑवर के भी बाकी है। आप लोग अगर दो-दो मिनट में उसको समाप्त कर देंगे तो मैं समझता हूं कि उसके बाद स्पेशल मेंशन भी लिए जा सकेंगे।

RE : SITUATION ARISING OUT OF — INDEFINITE HUNGER-STRIKE BE-FORE THE OFFICE OF THE 5TH PAY COMMISSION.

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार): माननीय उप-सभाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से एक विशेष महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। महोदय, आने वाले दिनों में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बहुत ही मुसीबत में फंसने वाली है और मैं आगाह करने के लिए और अनुरोध करने के लिए यह मुद्दा उठा रही हूं। पिछले तीन साल से पे-कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई। सेंट्रल गवर्नमेंट के 23 लाख एम्प्लाइज की इंटेरिम रिलीफ की जो डिमांड थी वह भी नहीं मिल पाई और इंटरिम रिलीफ की डिमांड के लिए पिछले दिनों से उनका आंदोलन जारी है। जोइंट कंसलटेटिव कमेटी मशीनरी के साथ पिछले दिनों एक समझौता हुआ था कि जुलाई के फर्स्ट वीक में यह इंटेरिम रिलीफ दे दिया जाएगा। पिछली सरकार जो थी, उस ने भी एनाउंसमेंट किया था कि इंटेरिम रिलीफ हम तत्काल दे देंगे लेकिन पांचवें पे-कमीशन ने तो उलटा ही काम किया। उन्होंने इंटेरिम रिलीफ देना तो दूर, उस पूरी बात को ही बदल कर और नए रेफरेंस के लिए सरकार को लिख दिया और गवर्नमेंट ने उस बात को मान भी लिया। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह हो गई कि इस के बाद जब जे.सी.एम. की बैठक हुई, उस बैठक में भी बात सुलझी नहीं। नतीजा यह है कि पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लायज के जो नुमाइंदे हैं, उन के नेता हैं, वे पे-कमीशन के सामने 8 जुलाई से अनशन पर हैं और देश के कोने-कोने से रोज-रोज आंदोलन, प्रदर्शन, धरने पर जा रहे हैं। किसी भी दिन हड़ताल पर जा सकते हैं लोग, अगर उनको इंटेरिम रिलीफ नहीं दिया गया तो। मेरा सरकार से निवेदन है कि जब तक पे-कमीशन अपनी रिपोर्ट पेश नहीं करता है जो कि आलरेडी ओवरड्यू है, एक साल ओवरड्यू हो गया, तब तक तुरंत इंटेरिम रिलीफ सरकार दे दे ताकि इस स्थिति से सरकार निपट सके नहीं तो फिर बात बिगड़ जाने पर एक दफा जब हड़ताल हो जाएगी तो फिर यकीन मानिए This country will come to a stand still और यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो जाएगी। आज के दिन में कहीं पर बाढ़ है, कहीं पर कोई प्राकृतिक आपदा आ रही है। जगह-जगह पर तरह-तरह की मुसीबतें आ रही हैं, इस हालत में अगर रेलगाड़ियां बंद हो जाएं, अगर हमारी फौज परेशानी में पड़े और दूसरे जो सरकारी कर्मचारी हैं, वे अगर परेशान हो कर हड़ताल पर जाने पर मजबूर हो जाएं तो देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे और तत्काल इस पर निर्णय ले कर इंटेरिम रिलीफ देने की एक-दो दिन के अंदर घोषणा करे क्योंकि हो सकता है कि अगले हफ्ते में हड़ताल शुरू हो जाए। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश): महोदय, पांचवे वेतन आयोग की अवधि सीमा 30 जून, 1996 तक बढ़ाई गई थी। अभी जो पता लगा है उस के अनुसार वेतन आयोग को कहा गया है कि वह अगस्त 1996 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। लेकिन प्रयास यह लगाए जा रहे हैं कि सरकार के दबाव की वजह से जिसकी नियति पर सभी लोगों को संदेह है, उस सरकार के दबाव की वजह से अगस्त 96 की समयावधि भी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और यही वजह है कि कर्मचारियों के मन में व्यापक असंतोष है, वे हड़ताल पर हैं। कई संगठनों ने काम बंद करने का मन बना लिया है। अत: यह आवश्यक है कि सरकार को स्पष्टत: वेतन आयोग को बताना चाहिए कि वह आवश्यक रूप से अगस्त, 96 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे और किसी भी दशा में इस समयावधि में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की जाएगी। कर्मचारियों के मन में जो संदेह व्याप्त हो गया है, उस को दूर करने कि लिए आवश्यक है कि सरकार को बजट में वेतन आयोग के लिए प्रावधान रखना चाहिए। पिछले समय सरकार ने कुछ जो कर्मचारी विरोधी घोषणाएं की हैं, उनकी मंशा यह दर्शाती है कि यह पुन: प्रयास किया जाएगा कि इस अगस्त, 96 की जो समयावधि है, उस को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी।